

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY FUTURISTIC DEVELOPMENT

आधुनिक नारी और वित्तीय स्वतन्त्रता: एक विश्लेषण

डॉ. रीता मौर्य

सहायक प्रोफेसर समाजशास्त्र, कन्या महाविद्यालय आर्य समाज, भूड़, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारत

* कॉर्रेस्पोंडिंग ऑथर: डॉ. रीता मौर्य

Article Info

P-ISSN: 3051-3618

E-ISSN: 3051-3626

Volume: 03

Issue: 01

Received: 14-12-2021

Accepted: 12-01-2022

Published: 10-02-2022

Page No: 79-83

सारांश

आधुनिक समाज में नारी की स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। शिक्षा, रोजगार, तकनीकी विकास, वैश्वीकरण तथा लोकतांत्रिक मूल्यों के विस्तार ने महिलाओं को पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं से आगे बढ़कर आर्थिक और सामाजिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्रदान किया है। इस परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वित्तीय स्वतन्त्रता है। वित्तीय स्वतन्त्रता का अर्थ केवल महिला की आय अर्जित करने की क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आय पर नियंत्रण, बचत, निवेश, बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच, वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता, संपत्ति पर अधिकार तथा आर्थिक जोखिमों से निपटने की क्षमता भी सम्मिलित है। भारत में महिला श्रम-बल भागीदारी, डिजिटल वित्तीय सेवाओं, स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म-वित्त तथा उद्यमिता के विस्तार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की संभावनाओं को बढ़ाया है। इसके बावजूद वेतन-असमानता, रोजगार की अस्थिरता, अवैतनिक देखभाल कार्य, संपत्ति के सीमित अधिकार, वित्तीय साक्षरता की कमी, डिजिटल विभाजन और सामाजिक रूढ़ियाँ महिलाओं की पूर्ण वित्तीय स्वतन्त्रता में बाधा बनी हुई हैं। प्रस्तुत शोध आलेख आधुनिक नारी की वित्तीय स्वतन्त्रता की अवधारणा, उसके सामाजिक एवं आर्थिक आयाम, शिक्षा और रोजगार की भूमिका, डिजिटल वित्तीय समावेशन, महिला उद्यमिता तथा वित्तीय निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी का विश्लेषण करता है। अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष यह है कि वास्तविक महिला सशक्तीकरण के लिए केवल महिलाओं की आय में वृद्धि पर्याप्त नहीं है; आय, संसाधनों और आर्थिक निर्णयों पर उनका स्वतंत्र नियंत्रण आवश्यक है। अतः वित्तीय स्वतन्त्रता को लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जाना चाहिए।

DOI: <https://doi.org/10.54660/IJMF.D.2022.3.1.79-83>

कुंजीशब्द: आधुनिक नारी, वित्तीय स्वतन्त्रता, महिला सशक्तीकरण, वित्तीय समावेशन, महिला उद्यमिता

परिचय

इक्कीसवीं सदी में नारी की सामाजिक और आर्थिक भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देता है। पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका मुख्यतः परिवार, घरेलू कार्य, बच्चों के पालन-पोषण और पारिवारिक दायित्वों से जुड़ी रही है। यद्यपि भारतीय इतिहास में महिलाओं की शिक्षा, प्रशासन, व्यापार और सामाजिक नेतृत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं, फिर भी लंबे समय तक आर्थिक संसाधनों और संपत्ति पर महिलाओं का नियंत्रण सीमित रहा। आधुनिकता, शिक्षा, औद्योगीकरण, नगरीकरण, लोकतांत्रिक चेतना और वैश्वीकरण ने इस स्थिति को धीरे-धीरे बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज महिला केवल परिवार की आश्रित सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षिका, चिकित्सक, वैज्ञानिक, प्रशासक, उद्यमी, बैंककर्मी, किसान, श्रमिक, तकनीकी विशेषज्ञ और स्वतंत्र पेशेवर के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रही है। महिला सशक्तीकरण के अनेक आयाम हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक सम्मान और कानूनी अधिकार महत्वपूर्ण हैं। इन सभी के बीच वित्तीय स्वतन्त्रता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक संसाधनों तक पहुँच व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। जिस महिला के पास अपनी आय, बचत, बैंक खाता, निवेश और संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसके लिए अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में स्वतंत्र भूमिका निभाना अपेक्षाकृत आसान होता है।

इसके विपरीत, आर्थिक निर्भरता अनेक बार महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करती है तथा उन्हें घरेलू और सामाजिक परिस्थितियों में असमान शक्ति-संबंधों को स्वीकार करने के लिए विवश कर सकती है। वित्तीय स्वतन्त्रता को केवल नौकरी करने या आय प्राप्त करने के अर्थ में देखना पर्याप्त नहीं है। एक महिला आय अर्जित कर सकती है, लेकिन यदि उसकी आय पर उसका नियंत्रण नहीं है तो उसकी आर्थिक स्वतन्त्रता सीमित रह सकती है। इसी प्रकार बैंक खाता होना वित्तीय समावेशन का संकेत हो सकता है, लेकिन यदि महिला बैंकिंग सेवाओं का स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर पाती या वित्तीय निर्णयों में उसकी भागीदारी नहीं है तो वास्तविक वित्तीय सशक्तीकरण अधूरा रहता है। इसलिए वित्तीय स्वतन्त्रता में आय, संपत्ति, बचत, ऋण, निवेश, वित्तीय ज्ञान, डिजिटल वित्तीय सेवाओं और निर्णय लेने की क्षमता को सम्मिलित रूप से समझना आवश्यक है। भारत में स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म-वित्त संस्थाओं, जन-धन खातों, डिजिटल भुगतान प्रणालियों और महिला उद्यमिता कार्यक्रमों ने महिलाओं के लिए आर्थिक अवसरों का विस्तार किया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह महिलाओं को बचत, ऋण, लघु उद्यम और सामूहिक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का माध्यम बने हैं। डिजिटल तकनीक ने बैंकिंग और भुगतान सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया है, हालांकि डिजिटल साक्षरता और तकनीकी पहुँच में मौजूद लैंगिक अंतर अभी भी एक चुनौती है। आधुनिक नारी की वित्तीय स्वतन्त्रता इसलिए केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक परिवर्तन का विषय है। आर्थिक रूप से सक्षम महिला परिवार की आर्थिक स्थिरता में योगदान देती है, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश को प्रभावित करती है तथा सामाजिक निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाती है। इस दृष्टि से महिला की वित्तीय स्वतन्त्रता परिवार, समाज और अर्थव्यवस्था के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करती है।

शिक्षा और वित्तीय स्वतन्त्रता का संबंध

महिला वित्तीय स्वतन्त्रता की आधारभूत शर्तों में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा महिला को केवल रोजगार प्राप्त करने की क्षमता ही प्रदान नहीं करती, बल्कि उसे आर्थिक संस्थाओं, अधिकारों, अवसरों और जोखिमों को समझने की क्षमता भी देती है। शिक्षित महिला बैंकिंग सेवाओं, ऋण, बीमा, निवेश, डिजिटल भुगतान और सरकारी आर्थिक योजनाओं का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकती है। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। उच्च शिक्षा महिलाओं के लिए औपचारिक रोजगार तथा पेशेवर क्षेत्रों के द्वार खोलती है। हालांकि केवल शैक्षणिक योग्यता वित्तीय स्वतन्त्रता सुनिश्चित नहीं करती। शिक्षा और रोजगार के बीच मौजूद अंतर, रोजगार में लैंगिक भेदभाव तथा घरेलू दायित्व महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए महिला शिक्षा को रोजगारोन्मुखी कौशल, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल दक्षता से जोड़ना आवश्यक है। विद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यक्तिगत वित्त, बैंकिंग, बचत, निवेश, कराधान और डिजिटल वित्त से संबंधित बुनियादी ज्ञान महिलाओं की दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता को मजबूत कर सकता है।

रोजगार और आय अर्जन में महिलाओं की भागीदारी

वित्तीय स्वतन्त्रता का सबसे प्रत्यक्ष माध्यम रोजगार और आय अर्जन है। नियमित रोजगार महिला को स्वयं की आय उपलब्ध कराता है तथा उसके आर्थिक आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आधुनिक समय में

महिलाएँ सरकारी सेवाओं, निजी क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, मीडिया और विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। फिर भी महिला रोजगार के सामने अनेक संरचनात्मक चुनौतियाँ हैं। महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी पर घरेलू कार्य, बच्चों और वृद्धों की देखभाल, सुरक्षित परिवहन का अभाव, कार्यस्थल की परिस्थितियाँ और सामाजिक मान्यताएँ प्रभाव डालती हैं। इसके अतिरिक्त अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को रोजगार सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और पर्याप्त आय जैसी सुविधाएँ सीमित रूप में प्राप्त होती हैं। वेतन असमानता भी वित्तीय स्वतन्त्रता की महत्वपूर्ण चुनौती है। समान या समान प्रकृति के कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम पारिश्रमिक मिलने की स्थिति उनके दीर्घकालीन आर्थिक संसाधनों को प्रभावित करती है। इसलिए महिला वित्तीय स्वतन्त्रता के लिए रोजगार की संख्या के साथ-साथ रोजगार की गुणवत्ता, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की समानता पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

महिला उद्यमिता और आर्थिक आत्मनिर्भरता

महिला उद्यमिता वित्तीय स्वतन्त्रता का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। छोटे व्यवसाय, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि-आधारित गतिविधियाँ, ऑनलाइन व्यवसाय, घरेलू उद्योग और सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। उद्यमिता महिलाओं को केवल आय का साधन नहीं देती बल्कि उत्पादन, विपणन, वित्त और प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने का अवसर भी प्रदान करती है। स्वयं सहायता समूहों ने विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नियमित बचत और समूह आधारित ऋण व्यवस्था ने अनेक महिलाओं को छोटे व्यवसाय प्रारंभ करने में सहायता प्रदान की है। इससे आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ सामूहिक नेतृत्व और सामाजिक सहभागिता की भावना भी विकसित होती है। हालांकि महिला उद्यमियों को पूँजी की उपलब्धता, बाजार तक पहुँच, तकनीकी ज्ञान, व्यवसाय प्रबंधन, डिजिटल विपणन और संपार्श्विक की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता के साथ प्रशिक्षण, बाजार संपर्क, तकनीकी सहायता और व्यवसायिक परामर्श आवश्यक है।

डिजिटल वित्तीय समावेशन और आधुनिक नारी

डिजिटल तकनीक ने वित्तीय सेवाओं की प्रकृति को व्यापक रूप से बदल दिया है। मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग और वित्तीय तकनीक ने बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच को अधिक सरल बनाया है। महिलाओं के लिए डिजिटल वित्तीय सेवाएँ विशेष महत्व रखती हैं क्योंकि इनके माध्यम से वे अपने बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन पर अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त कर सकती हैं। भारत में वित्तीय समावेशन के विस्तार के साथ बैंक खातों की पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विश्व बैंक के Global Findex के अनुसार भारत में खाता स्वामित्व और डिजिटल भुगतान के उपयोग में पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह परिवर्तन महिलाओं के आर्थिक जीवन के लिए भी अवसर पैदा करता है।

हालांकि डिजिटल वित्तीय समावेशन के सामने डिजिटल साक्षरता, स्मार्टफोन तक पहुँच, इंटरनेट की उपलब्धता और साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं। ग्रामीण और निम्न-आय वर्ग की महिलाओं के लिए इन बाधाओं का प्रभाव अधिक हो सकता है। इसलिए डिजिटल बैंकिंग को केवल तकनीकी सुविधा के रूप में नहीं बल्कि डिजिटल वित्तीय साक्षरता के साथ विकसित करना आवश्यक है।

संपत्ति, बचत और निवेश पर महिलाओं का अधिकार

वित्तीय स्वतन्त्रता का एक महत्वपूर्ण आयाम संपत्ति और वित्तीय परिसंपत्तियों पर महिला का अधिकार है। भूमि, घर, बैंक जमा, बीमा, पेंशन और निवेश जैसी परिसंपत्तियाँ महिला की दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करती हैं। नियमित आय होने के बावजूद यदि महिला के पास व्यक्तिगत बचत या संपत्ति नहीं है तो आर्थिक संकट की स्थिति में उसकी निर्भरता बनी रह सकती है। महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को वित्तीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। बचत के साथ-साथ सुरक्षित निवेश और बीमा की जानकारी महिलाओं को भविष्य के जोखिमों से निपटने में सहायता करती है। विशेष रूप से वृद्धावस्था, स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिकता और पारिवारिक आर्थिक संकट के समय व्यक्तिगत वित्तीय संसाधन महिला की सुरक्षा बढ़ाते हैं। इस संदर्भ में वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है। महिलाओं को बचत और निवेश के विभिन्न साधनों के जोखिम, लाभ और अवधि की जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है। संपत्ति के कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता भी महिला की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

परिवार में वित्तीय निर्णय और महिला की भूमिका

वित्तीय स्वतन्त्रता का वास्तविक प्रभाव परिवार के भीतर महिला की निर्णय क्षमता में दिखाई देता है। परिवार की आय और व्यय से जुड़े निर्णयों में महिला की भागीदारी उसकी आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक है। शिक्षा, बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य, आवास, बचत और निवेश से संबंधित निर्णयों में महिला की भागीदारी परिवार के संसाधनों के अधिक संतुलित उपयोग को बढ़ावा दे सकती है। परिवार में महिला की आर्थिक भागीदारी बढ़ने से पारंपरिक शक्ति-संबंधों में भी परिवर्तन आता है। आय अर्जित करने वाली महिला परिवार के आर्थिक निर्णयों में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती है। लेकिन यहाँ भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि रोजगार और आय अपने आप निर्णय-स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देते। कई परिवारों में महिला की आय को परिवार की सामूहिक आय माना जाता है जबकि उसके व्यक्तिगत वित्तीय निर्णयों की स्वतंत्रता सीमित रह सकती है। इसलिए वित्तीय सशक्तीकरण का मूल्यांकन केवल महिला की आय से नहीं बल्कि उसके संसाधनों पर नियंत्रण और निर्णय लेने की वास्तविक क्षमता से किया जाना चाहिए।

साहित्य समीक्षा

अमर्त्य सेन (1999) ने Development as Freedom में विकास को केवल आय और आर्थिक वृद्धि के बजाय मानव स्वतंत्रता तथा क्षमताओं के विस्तार से जोड़ा। उनके क्षमता दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता इस बात से निर्धारित होती है कि उसके पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन के संबंध में कितने विकल्प चुनने की क्षमता है। महिला वित्तीय स्वतन्त्रता के संदर्भ में यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी महिला के पास आय या बैंक खाता होना उसकी आर्थिक स्थिति का एक संकेतक हो सकता है, लेकिन वास्तविक सशक्तीकरण तब दिखाई देता है जब वह अपनी आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बचत और भविष्य से जुड़े निर्णयों में स्वतंत्र भूमिका निभा सके।

नाइला कबीर (1999) ने महिला सशक्तीकरण की अवधारणा को संसाधनों, एजेंसी और उपलब्धियों के परस्पर संबंध के आधार पर समझाया। उनके अध्ययन का केंद्रीय तर्क यह है कि महिलाओं को केवल आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन संसाधनों के उपयोग और उनसे संबंधित निर्णय लेने की क्षमता भी आवश्यक है। इस दृष्टिकोण से वित्तीय स्वतन्त्रता को महिला की आय तक सीमित नहीं किया जा सकता। यदि महिला रोजगार के

माध्यम से आय अर्जित करती है लेकिन उस आय पर उसका स्वतंत्र नियंत्रण नहीं है, तो उसकी आर्थिक स्वतन्त्रता सीमित रह सकती है। **मेयूक्स (2001)** ने महिला सशक्तीकरण और माइक्रो-फाइनेंस के संबंध का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया कि वित्तीय सेवाओं तक पहुँच महिलाओं के आर्थिक अवसरों को बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम हो सकती है। विशेष रूप से निम्न आय वर्ग की महिलाओं के लिए बचत और छोटे ऋण आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करने, छोटे व्यवसाय विकसित करने तथा घरेलू आय में योगदान करने के अवसर पैदा कर सकते हैं।

कुमारी एवं मिश्रा (2015) ने वाराणसी जिले के संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों और महिला विकास के बीच संबंध का अध्ययन किया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अध्ययन से संकेत मिलता है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को नियमित बचत, सामूहिक ऋण, छोटे स्तर की आर्थिक गतिविधियों तथा आय-सृजन के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। समूह आधारित वित्तीय गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं में आर्थिक आत्मविश्वास और सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है।

डेमिरगु (2018) ने The Global Index Database 2017 के माध्यम से विश्वभर में वित्तीय समावेशन, बैंक खातों, बचत, ऋण और डिजिटल वित्तीय सेवाओं की स्थिति का व्यापक अध्ययन किया। अध्ययन ने यह रेखांकित किया कि औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच आर्थिक अवसरों और वित्तीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। महिलाओं और पुरुषों के बीच वित्तीय पहुँच में मौजूद अंतर को कम करना समावेशी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना गया। डिजिटल तकनीक के विस्तार ने बैंकिंग और भुगतान सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की संभावनाएँ पैदा की हैं।

अनुसंधान अंतराल

उपलब्ध साहित्य में महिला सशक्तीकरण, रोजगार और वित्तीय समावेशन पर पर्याप्त अध्ययन उपलब्ध हैं, लेकिन आधुनिक नारी की वित्तीय स्वतन्त्रता को आय, वित्तीय निर्णय, डिजिटल वित्तीय पहुँच, संपत्ति अधिकार, निवेश व्यवहार और सामाजिक मान्यताओं के संयुक्त परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता बनी हुई है। विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के बाद महिला वित्तीय स्वतन्त्रता का स्वरूप बदल रहा है। बैंक खाता और डिजिटल भुगतान तक पहुँच बढ़ने के बावजूद वित्तीय ज्ञान, संसाधनों पर नियंत्रण और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता में असमानताएँ बनी हुई हैं। इसलिए आधुनिक भारतीय महिला की वित्तीय स्वतन्त्रता को केवल रोजगार या आय के आधार पर नहीं बल्कि बहुआयामी दृष्टिकोण से समझना आवश्यक है।

अध्ययन के उद्देश्य

- आधुनिक नारी के संदर्भ में वित्तीय स्वतन्त्रता की अवधारणा का विश्लेषण करना।
- महिला शिक्षा और रोजगार का वित्तीय स्वतन्त्रता पर प्रभाव समझना।
- महिला उद्यमिता और स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक भूमिका का अध्ययन करना।
- डिजिटल वित्तीय समावेशन और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी के संबंध का विश्लेषण करना।
- महिलाओं के वित्तीय निर्णय, संपत्ति अधिकार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना।
- शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें आधुनिक नारी की वित्तीय स्वतन्त्रता को सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है। अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, जिनमें सरकारी रिपोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट, शोध-अध्ययन तथा महिला आर्थिक सशक्तीकरण से संबंधित प्रमाणित साहित्य सम्मिलित हैं। अध्ययन में वित्तीय स्वतन्त्रता के प्रमुख आयामों के रूप में आय, रोजगार, बचत, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, निवेश, संपत्ति अधिकार, वित्तीय निर्णय तथा उद्यमिता को लिया गया है। उपलब्ध साहित्य का विषयगत विश्लेषण करके आधुनिक महिला की आर्थिक स्थिति तथा वित्तीय स्वतन्त्रता के बीच संबंध को समझने का प्रयास किया गया है। अध्ययन में

प्राथमिक सर्वेक्षण न होने के कारण कोई काल्पनिक सर्वेक्षण प्रतिशत या सांख्यिकीय परिणाम प्रस्तुत नहीं किया गया है।

डेटा विश्लेषण और व्याख्या

महिलाओं की वित्तीय स्वतन्त्रता को समझने के लिए केवल एक आर्थिक संकेतक पर्याप्त नहीं है। विभिन्न संस्थागत स्रोतों से उपलब्ध जानकारी यह दर्शाती है कि महिला वित्तीय समावेशन में बैंक खातों, डिजिटल भुगतान, रोजगार और उद्यमिता की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण हो रही है। विशेष रूप से डिजिटल वित्तीय सेवाओं का विस्तार महिलाओं के लिए औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। फिर भी वित्तीय पहुँच और वित्तीय नियंत्रण के बीच अंतर को समझना आवश्यक है।

तालिका 1: महिला वित्तीय स्वतन्त्रता के प्रमुख आयामों का तुलनात्मक विश्लेषण

आयाम	वित्तीय स्वतन्त्रता में भूमिका	प्रमुख चुनौती
शिक्षा	वित्तीय ज्ञान और रोजगार क्षमता बढ़ाती है	गुणवत्तापूर्ण एवं वित्तीय शिक्षा तक असमान पहुँच
रोजगार	नियमित व्यक्तिगत आय उपलब्ध कराता है	रोजगार में लैंगिक अंतर और असमान वेतन
बैंक खाता	औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ता है	खाते के स्वतंत्र उपयोग की कमी
डिजिटल भुगतान	तेज और प्रत्यक्ष वित्तीय लेन-देन की सुविधा	डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा
बचत	आर्थिक संकट के समय सुरक्षा प्रदान करती है	कम और अनियमित आय
निवेश	दीर्घकालीन संपत्ति निर्माण में सहायक	निवेश ज्ञान और जोखिम संबंधी जानकारी की कमी
संपत्ति अधिकार	दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा बढ़ाता है	सामाजिक परंपराएँ और जागरूकता की कमी
उद्यमिता	आय तथा निर्णय क्षमता दोनों बढ़ाती है	पूँजी, बाजार और तकनीकी ज्ञान की कमी
स्वयं सहायता समूह	सामूहिक बचत और ऋण तक पहुँच	सीमित व्यवसायिक विस्तार
वित्तीय निर्णय	वास्तविक आर्थिक एजेंसी का संकेत	पारिवारिक शक्ति-संबंध

व्याख्या: उपर्युक्त तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वित्तीय स्वतन्त्रता बहुआयामी प्रक्रिया है। केवल बैंक खाता या रोजगार होना पर्याप्त नहीं है। आर्थिक स्वतन्त्रता तब अधिक प्रभावी होती है जब महिला के पास आय के साथ-साथ बचत, संपत्ति, वित्तीय ज्ञान और आर्थिक निर्णयों पर वास्तविक नियंत्रण भी हो।

वित्तीय स्वतन्त्रता की प्रमुख चुनौतियाँ

आधुनिक नारी की आर्थिक स्थिति में सुधार के बावजूद अनेक चुनौतियाँ बनी हुई हैं। पहली चुनौती अवैतनिक घरेलू और देखभाल कार्य है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घरेलू श्रम अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होने के बावजूद सामान्यतः प्रत्यक्ष आय के रूप में दिखाई नहीं देता। इससे महिलाओं के पास रोजगार और आय अर्जित करने के लिए उपलब्ध समय सीमित होता है। दूसरी चुनौती रोजगार की गुणवत्ता है। अनौपचारिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएँ कार्य करती हैं जहाँ सामाजिक सुरक्षा, स्थायी आय और रोजगार सुरक्षा सीमित हो सकती है। तीसरी चुनौती वित्तीय साक्षरता है। बैंक खाता होने के बावजूद यदि महिला बचत, ऋण, निवेश, बीमा और डिजिटल सुरक्षा से संबंधित निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाती तो वित्तीय समावेशन अधूरा रहता है। चौथी चुनौती सामाजिक मान्यताओं से जुड़ी है। कई परिवारों में महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिकता नहीं दी जाती। महिलाओं की गतिशीलता, व्यवसाय चयन और वित्तीय निर्णयों पर पारिवारिक नियंत्रण उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

अध्ययन की सीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, इसलिए इसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र की महिलाओं का प्राथमिक सर्वेक्षण शामिल नहीं किया गया है। भारत में महिलाओं की आर्थिक स्थिति राज्य, ग्रामीण-शहरी क्षेत्र, शिक्षा, आय-वर्ग और सामाजिक परिस्थितियों के

आधार पर भिन्न होती है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर के निष्कर्षों को प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उपलब्ध स्रोतों में वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तीकरण के अलग-अलग संकेतकों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण प्रत्यक्ष तुलनात्मक विश्लेषण की सीमा बनी रहती है। इसके अतिरिक्त वित्तीय स्वतन्त्रता का एक महत्वपूर्ण पक्ष महिलाओं के वित्तीय निर्णयों पर वास्तविक नियंत्रण से संबंधित है, जिसे केवल आय या बैंक खाते जैसे मात्रात्मक संकेतकों से पूरी तरह मापना कठिन है। भविष्य के अध्ययन में ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच तुलनात्मक प्राथमिक सर्वेक्षण, आयु एवं शिक्षा आधारित विश्लेषण तथा डिजिटल वित्तीय व्यवहार के अध्ययन से विषय की अधिक व्यापक समझ विकसित की जा सकती है।

अध्ययन का महत्व

आधुनिक नारी की वित्तीय स्वतन्त्रता का अध्ययन सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से सक्षम महिला परिवार की आय में योगदान करने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, बचत और भविष्य की योजनाओं से संबंधित निर्णयों में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती है। महिला की वित्तीय क्षमता बढ़ने से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है। व्यापक आर्थिक दृष्टि से महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी और उद्यमिता में वृद्धि मानव संसाधन के अधिक प्रभावी उपयोग को संभव बनाती है। वित्तीय स्वतन्त्रता महिलाओं को आर्थिक संकटों के प्रति अधिक सक्षम बनाती है तथा उन्हें सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों में अधिक स्वतंत्र विकल्प प्रदान करती है। इसलिए महिला वित्तीय सशक्तीकरण को केवल कल्याणकारी नीति के रूप में नहीं बल्कि समावेशी और सतत आर्थिक विकास की रणनीति के रूप में देखना चाहिए।

निष्कर्ष

आधुनिक नारी की वित्तीय स्वतन्त्रता समकालीन समाज में महिला सशक्तीकरण का एक केंद्रीय आधार बन चुकी है। आज महिला की पहचान केवल परिवार की भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आर्थिक उत्पादन, व्यवसाय, प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और सामाजिक नेतृत्व के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी निभा रही है। इस परिवर्तन के बावजूद वास्तविक वित्तीय स्वतन्त्रता अभी भी एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। महिला का रोजगार में होना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसे अपनी आय, बचत, संपत्ति और वित्तीय निर्णयों पर वास्तविक अधिकार प्राप्त हो। शिक्षा महिलाओं को वित्तीय अवसरों को समझने की क्षमता देती है, रोजगार आय का आधार प्रदान करता है, उद्यमिता आर्थिक निर्णय क्षमता को बढ़ाती है तथा डिजिटल वित्तीय सेवाएँ औपचारिक वित्तीय व्यवस्था तक पहुँच को आसान बनाती हैं। स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म-वित्त जैसी संस्थागत व्यवस्थाएँ विशेष रूप से ग्रामीण एवं निम्न-आय वर्ग की महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर पैदा कर सकती हैं। फिर भी इन साधनों का प्रभाव तभी स्थायी होगा जब महिलाओं को वित्तीय साक्षरता, डिजिटल सुरक्षा, बाजार तक पहुँच और संपत्ति अधिकारों की जानकारी भी उपलब्ध हो। अतः महिला वित्तीय स्वतन्त्रता के लिए ऐसी समग्र नीतियों की आवश्यकता है जो शिक्षा, कौशल, रोजगार, समान पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता और संपत्ति अधिकारों को एक साथ संबोधित करें। परिवार और समाज के स्तर पर भी महिलाओं के आर्थिक निर्णयों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। वास्तविक महिला सशक्तीकरण तब संभव होगा जब महिला केवल आय अर्जित करने वाली नहीं बल्कि अपनी आर्थिक दिशा स्वयं निर्धारित करने वाली नागरिक बने। इस अर्थ में वित्तीय स्वतन्त्रता आधुनिक नारी की आत्मनिर्भरता, गरिमा और समान नागरिकता का महत्वपूर्ण आधार है।

संदर्भ सूची

1. कबीर नायला. महिला सशक्तीकरण के मापन पर संसाधन, एजेंसी और उपलब्धियों का विश्लेषण. विकास और परिवर्तन. 1999;30(3):435-464.
2. मेयूक्स लिंडा. सामाजिक पूँजी, महिला सशक्तीकरण और माइक्रो-फाइनेंस का विश्लेषण: कैमरून का अध्ययन. विकास और परिवर्तन. 2001;32(3):435-464.
3. पिट मार्क एम, खांडकर शाहिदुर आर, कार्टराइट जेनिफर. माइक्रो-फाइनेंस के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण: बांग्लादेश के प्रमाण. आर्थिक विकास और सांस्कृतिक परिवर्तन. 2006;54(4):791-831.
4. दुप्लो एस्थर. महिला सशक्तीकरण और आर्थिक विकास. आर्थिक साहित्य पत्रिका. 2012;50(4):1051-1079.
5. घोष रत्ना, चक्रवर्ती पारोमिता, मंसी कुमारी. भारत में शिक्षा, पंचायती राज और महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण. शिक्षा में नीति भविष्य. 2015;13(3):294-314.
6. निथ्यानंदन एस हेमवती, मंसूर नॉर्मा. स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तीकरण. संस्थाएँ और अर्थव्यवस्थाएँ. 2015;7(2):144-165.
7. कुमारी त्रिप्ती, मिश्रा आनंद प्रसाद. स्वयं सहायता समूह और महिला विकास: वाराणसी जिले का अध्ययन. अंतरिक्ष और संस्कृति, भारत. 2015;2(4):35-48.

8. सिंह इकबाल, लांबा पायल. भारत में महिला उद्यमिता. अकादमिकिया: एक अंतरराष्ट्रीय बहुविषयक शोध पत्रिका. 2016;6(5):211-217.
9. खोखर अमित सिंह. भारत में महिला उद्यमिता को निर्धारित करने वाले कारक. उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उद्यमिता और नवाचार पत्रिका. 2019;5(2):180-197.
10. समंताराय एलीना, तोमर जे एस. भारत में महिला उद्यमिता: आर्थिक जनगणनाओं से प्राप्त प्रमाण. सामाजिक परिवर्तन. 2018;48(2):188-207.
11. डेमिग्यूच-कुंत असली, क्लैपर लिथोरा, सिंगर डोरोथी, अंसार सानिया, हेस जेक. ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2017: वित्तीय समावेशन और फिनटेक क्रांति का मापन. विश्व बैंक; 2018.
12. कौर सिमरित, कपूरिया चेशता. ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के निर्धारक: क्या लैंगिकता मायने रखती है? अंतरराष्ट्रीय सामाजिक अर्थशास्त्र पत्रिका. 2020;47(6):747-767.
13. रिक उटे, वाले याबिबल एम, क्लासेन स्टीफन. वित्तीय साक्षरता में लैंगिक अंतर और संस्कृति की भूमिका. अर्थशास्त्र और वित्त की त्रैमासिक समीक्षा. 2021;80:117-134.
14. सामंता तनिष्ठा. महिला सशक्तीकरण और आत्म-करुणा: भारत से प्राप्त अनुभवजन्य प्रमाण. पीएलओएस वन. 2020;15(5):e0232526.
15. सेन अमर्त्य. विकास का स्वतंत्रता के रूप में स्वरूप. ऑक्सफोर्ड: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 1999.